

श्री उपसभापति : आपके बोलने का समय खत्म हो गया है। माननीय विक्रमजीत सिंह साहनी जी आपके पास सिर्फ तीन मिनट का समय था।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Vikramjit Singh Sahney: Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri M. Mohamed Abdulla and Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh).

Now, Shri Sakaldeep Rajbhar, 'Need to create job opportunities for youth by establishing different industries in the State of Bihar.'

Need to create job opportunities for youth by establishing different industries in the State of Bihar

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, आज हम इस अमृतकाल में बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि यहां के माननीय जयप्रकाश नारायण जी, देश के पूर्व प्रधान मंत्री चंद्र शेखर जी, देश के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी एवं चित्तू पांडेय, मंगल पांडे और वीर कुंवर सिंह आज के अनेक अमर शहीद, जिन्होंने बलिया को सबसे पहले लड़ कर आज़ाद कराया। जहां गंगा और सरस्वती नदियों का संगम होता है, ऐसा क्षेत्र आज विकास विहीन है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी क्षेत्र एवं कुछ झारखंड के क्षेत्र में आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी कोई फैक्टरी या कारखाना अथवा भारी उद्योग नहीं है। कोई देश-विदेश से निवेश करने वाला भी नहीं है। यह बिल्कुल ही पिछड़ा व अनदेखा क्षेत्र है। आज स्थिति यह है कि उक्त क्षेत्र के शिक्षित-अशिक्षित बेरोज़गार नौजवान अपनी गरीबी की वजह से अपना पेट पालने, अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए देश के मेट्रो शहरों में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पंजाब एवं हरियाणा के अनेक शहरों में जीविकोपार्जन के लिए रोज़गार की तलाश के लिए अपना घर-परिवार छोड़कर बाहर जाता है। यही नहीं, वह अपने बाल-बच्चों को 2-2, 3-3 साल के लिए परिवार से नाता तोड़कर कुछ पैसा कमाता है और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए भेजता है, लेकिन वह यह नहीं जान पाता है कि उसके बाल-बच्चों की पढ़ाई-लिखाई या भरण-पोषण ठीक-ठाक हो रहा है अथवा नहीं। परिवार से लगाव टूटने की वजह से बाल बच्चों की शिक्षा-दीक्षा ठीक से नहीं हो पाती है और उसके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब ही रह जाते हैं। भुखमरी और बेरोज़गारी का अंदाज़ा तब लगता है, जब ट्रेन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से शहरों की ओर जाती है। माननीय महोदय, ऐसी सूरत में अविकसित और विषम परिस्थितियों को देखते हुए इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि उनके क्षेत्र में कल-कारखाना, फैक्टरी, मिल या कोई भारी उद्योग होता, तो वहां के नौजवानों को मेट्रो शहरों में

विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता और वे अपने परिवार के साथ रहकर अपने बाल-बच्चों का सही लालन-पालन करते, जिससे उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी होता।

अतः माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार और राज्य सरकारों से मांग करता हूँ कि उक्त क्षेत्रों में भारी उद्योग या कल-कारखाना और देशी-विदेशी निवेशकों से निवेश कराने की कृपा करें, जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके।...(समय की घंटी)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Sakaldeep Rajbhar: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

माननीय सदस्यगण, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बोलें, उस पर पहले से तैयार लिखित भाषण न पढ़ें। श्री अब्दुल वहाब जी; Demand to include all *Navodaya Vidhyalaya* employees under CCS Pension Scheme.

Demand to include all Navodaya Vidyalaya employees under CCS pension scheme

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, the *Navodaya Vidhyalaya* since 1985 has been there all over India. It is a wonderful experiment and it has won a lot of sidelined rural students. Nowadays, after passing out from the *Navodaya*, they are in good positions. The issue is that the teachers and the employees are not in this pension scheme. Over the last several years, this matter is being raised. Even the parliamentary committee has given its recommendation. But it is still with the Finance Department. Thousands of employees are waiting for this to happen. All other institutions are being given pension and other facilities by the Government of India. But, why is this lagging behind? That is my point. Hence, I hope that before they would come out with 'Chalo Parliament' and Parliament blockade, please consider this one as early as possible. That is my demand. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shri Abdul Wahab: Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Jose K. Mani (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Binoy Viswam (Kerala), Shri Sandosh Kumar P. (Kerala), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Jayant Chaudhary (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Shri M. Mohamed Abdulla and Dr. Amar Patnaik (Odisha).